

जुर्नाना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनियुक्तगण को जरिये सम्मान तलब किया गया। अनियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अनियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा अनियुक्त को पुलिस का डर दिखाकर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। जिसका आवेदक द्वारा नमूने उपयोग किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त नमूने की कार्यवाही अनियुक्त के समक्ष नहीं की गई है जो कि अनियुक्त को कय खाद्य पदार्थ का कोई मुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत व कर्त्तव्य तर्क से की गई है। अनियुक्त एक किराये की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अनियुक्त ने अनियुक्त के प्रति नरमी रख अपनाते हुए उक्त प्रकरण कार्यवाही द्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अनियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हम ही पत्रावली में संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1717/एक्ट/2021/1580 दिनांक 25.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक खाद्य वस्तु नावा बर्फी (नावा चीनी एवं मिस्टा से निर्मित) का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। लेकिन यदि अनियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेकरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयवधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनियुक्तगण के विकरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अनियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियुक्तगण के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अनियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रु० की आर्थिक शास्ति से अधिराहित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अनियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चलाने जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला नजिस्ट्रेट, गंगानगर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुलामन नियाद अमोल नियमानुसार वचूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अनियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला नजिस्ट्रेट
गंगानगर सिटी,
अतिरिक्त जिला नजिस्ट्रेट एवं
गंगानगर सिटी